Patrika (Indore), 16th January 2026, Page – 13 (Front Page – plus 05)

तैयारी

स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च को मिलेगी नई उड़ान

स्पेस टेक नीति से इंदौर बनेगा प्रदेश का टेक्नोलॉजी हब

सुरभि भावसार
patrika.com

इंदौर. प्रदेश की पहली स्पेस टेक्नोलॉजी नीति लागू होते ही इंदौर राज्य का सबसे बड़ा लाभार्थी शहर बनकर उभर सकता है। मजबूत रिसर्च संस्थान, सक्रिय स्टार्टअप इकोसिस्टम, विकसित मैन्युफैक्चरिंग आधार के कारण इंदौर इस नीति का प्राकृतिक केंद्र बन सकता है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी (आरआरकैट) और आइआइटी इंदौर जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान तकनीकी रीढ़ बनेंगे, जबकि फोकस कृषि, और नवाचार और स्टार्टअप पर रहेगा।

स्पेस टेक नीति का रोडमैप

यह प्रदेश की पहली समर्पित स्पेस टेक नीति है, जिसे एमपीडीसी के माध्यम से तैयार किया गया है। नीति का उद्देश्य केवल अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी के व्यावहारिक और सामाजिक उपयोग को बढ़ावा देना है।

इन क्षेत्रों में प्रमुख फोकस

1. कृषि में स्पेस टेक का उपयोग
2. स्पेस सेक्टर से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
3. स्कूल-कॉलेज स्तर से स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रोत्साहन

आरआरकैट से ताकत तो आइआइटी बनेगा आधार

आरआरकैट पहले से ही फोटोनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, कंट्रोल सिस्टम और वैक्यूम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है, जो स्पेस सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आरआरकैट देश के महत्वाकांक्षी 'लाइगो इंडिया' प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी भी है। वहीं आइआइटी इंदौर में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस से जुड़ा रिसर्च पहले से मौजूद है। आरआरकैट के सहयोग से स्पेस ऑब्जर्वेशन, टेलिस्कोप नेटवर्क, खगोलीय अध्ययन पर काम हो रहा है। यह रिसर्च आधार भविष्य में डीप-टेक स्टार्टअप्स और स्पेस इनोवेशन को मजबूती देगा।

उज्जैन-सांवेर-देवास को भी लाभ

नीति के केंद्र उज्जैन क्षेत्र में विकसित हो सकते हैं, जो आइआइटी इंदौर के एक्सटेंशन या सहयोगी केंद्र के रूप में काम करेंगे। सांवेर और देवास के इंडस्ट्रियल एरिया की नजदीकी से पूरा क्षेत्र रीजनल क्लस्टर बन सकेगा।